

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र- चरण-II में प्रतस्पर्द्धा बढ़ाने की योजना

प्रलिस के लयि:

पूंजीगत सामान, प्रत्यक्ष वदिशी नविश, मुक्त व्यापार समझौता ।

मेन्स के लयि:

भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का महत्त्व, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप ।

चर्चा में क्यौं?

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र- चरण-II में प्रतस्पर्द्धा बढ़ाने की योजना की अधसूचना जारी कर दी है, ताकि सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसरचना को सहायता प्रदान की जा सके ।

प्रमुख बदि

■ परचिय:

- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतस्पर्द्धा बढ़ाने वाली इस योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य पहले चरण की प्रायोगिक योजना के प्रभाव को वसितार देना और उसे आगे बढ़ाना है । इस तरह वैश्विक स्तर पर प्रतस्पर्द्धा योग्य पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की मजबूत रचना करके उसमें तेज़ी लाई जाएगी । उल्लेखनीय है कयिह क्षेत्र नरिमाण क्षेत्र में कम से कम 25 प्रतिशत का योगदान करता है ।
- प्रौद्योगिकी विकास और बुनयिदी ढाँचे के नरिमाण को प्रोत्साहति करने हेतु नवंबर 2014 में 'भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतस्पर्द्धा में वृद्धि' योजना को अधसूचति कयिा गया था ।

■ वत्तीय परवियय:

- इस योजना में 975 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन और 232 करोड़ रुपए के उद्योग योगदान के साथ 1207 करोड़ रुपए का वत्तीय परवियय शामिल है ।

■ घटक:

- प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियिँ की पहचान ।
- चार नए 'उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों' की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का वसितार ।
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देना-कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लयि योगयता पैकेज बनाना ।
- चार 'कॉमन इंजीनयरिंग फैसलिति सेंटरस' (CEFCs) की स्थापना और मौजूदा CEFCs का संवर्द्धन ।
- मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का वसितार ।
- दस 'इंडस्ट्री एक्सेलरेटरस फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट' की स्थापना करना ।

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र:

■ पूंजीगत वस्तुएँ:

- पूंजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) भौतिक संपत्तयिँ हैं जनिहें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रयिा में उत्पादों और सेवाओं के नरिमाण हेतु उपयोग करती है तथा जनिका बाद में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग कयिा जाता है ।
- पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल हैं ।
- पूंजीगत वस्तुएँ तैयार माल नहीं होती बल्कि उनका उपयोग माल को नरिमति करने के लयि कयिा जाता है ।
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का गुणक प्रभाव होता है और उपयोगकर्त्ता उद्योगों के विकास पर इसका असर पडता है क्यौंकयिह वनरिमाण गतवधि के अंतर्गत आने वाले शेष क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण इनपुट, यानी मशीनरी और उपकरण प्रदान करता है ।

■ परदृश्य:

- पूंजीगत वस्तु उद्योग का कुल वनरिमाण गतवधि में 12% का योगदान है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8% है ।
- यह लगभग 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है ।

■ **संबंधित नीतियाँ:**

- इस क्षेत्र के लिये किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- स्वतः मार्ग (RBI के माध्यम से) पर 100% तक **प्रत्यक्ष वदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति है।
- वदेशी सहयोगी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, डज़ाइन और ड़राइंग, रॉयल्टी आदिके लिये भुगतान की मात्रा की कोई सीमा नहीं है।
- आमतौर पर **अधिकतम मूल सीमा शुल्क दर (maximum basic customs duty rate) 7.5-10%** है।
- भारत ने कई **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** दर्ज किये हैं, जसमें शुल्क की दरें और भी कम हैं तथा परियोजना आयात सुवधा के तहत कम शुल्क दरें भी उपलब्ध हैं।
- **वदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणज्य और उद्योग मंत्रालय** की वभिन्न योजनाओं के माध्यम से कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों एवं घटकों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देकर निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/scheme-on-enhancement-of-competitiveness-in-the-indian-capital-goods-sector-phase-ii>

